(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय सीमेंट निगम के कुल 11 कारखानों में से 6 को बंद कर दिया गया हैं और शेष 5 भी बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) पिछले पांच वर्षो के दौरान भारतीय सीमेंट निगम के कुल लाभ-हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल) : (क) और (ख) जी, नही। सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.4.96 को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित कर दिया गया था और बी.आई.एफ.आर. ने पहले से ही सीमेंट कारपोरेश आफ इंडिया के लिए एक मसौदा पुनरूद्वार योजना तैयार कर ली हैं तथा इसे सभी संबंधितों को उनके विचार जानने हेतु दिनांक 12.6.98 को पारिचालित कर दिया हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। केवल तीन इकाइयों अर्थात मांढर अकलतरा और चरखी दादरी में इन इकाइयों के अजैव्य होने के कारण उत्पादन को निदेशक मंडल के अनुमोदन से बंद कर दिया हैं।

(ड.) पिछले पांच वर्षो के दौरान उत्पादन. बिक्रियां तथा लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन में)	बिक्रिया (करोड़ रूपये में)	लाभ(+)/ हानि (-) (करोड़ रूपये में)
1994.95	21.89	401.46	(-) 149.96
1995.96	19.56	434.54	(-) 115.04
1996.97	17.20	405.10	(-) 159.41
1997.98 (अनंतिम)	9.85	240.93	(-) 97.54
1998.99 (अप्रैल-अक्तूबर, 98 अनंतिम)	6.19	130.16	(-) 106.35

कागज आधारित लद्यु उघोगों पर शुल्क लगाया जाना

51. **श्री शिबू सोरेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि रद्दी कागज के आयात पर पांच प्रतिशत के मूल शूल्क के कारण कागज और गत्ता बनाने वाली देश की लगभग 170 लघु उद्योग और अत्यंत लघु उद्योग इकाइंया बुरी तरह प्रभावित हो रही है, और

(ख) क्या यह भी सच हैं कि पांच लाख टन की स्थापित क्षमता वाली 110 रद्दी कागज की मिलें बंद हो चुकी हैं

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) कागज के मिलों के बंद होने से संबंधित राज्य-वार तथा वर्ष-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, यह बताया जाता हैं कि रद्दी कागज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाली लगभग 110 मिल विभिन्न कारणों से बंद पड़ी हैं।

Industrial development of North East

52. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the details of steps taken/ contemplated by Government to accelerate the pace of industrial development in the N.E. region in general and Assam in particular; and

(b) what has been/is the likely impact of each of these steps?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) To tackle the problem of industrial backwardness of NE region and attracting investment for setting up industrial units in the North East, a new industrial policy for the North Eastern Region was announced by the Government on December, 1997.

(b) With a view to promoting industrialisation, Nine Growth Centres are to be set up in the NE states including 3 for the state of Assam. Subsidy is provided under the transport subsidy scheme to reduce the extra transport cost and promote industrialisation of hilly, remote and inaccessible areas like North Eastern States. The Integrated Infrastructure Development (IID) scheme for setting up infrastructural facilities in backward/rural areas of the country also includes North Eastern Region. Since inception of the Scheme till 31.3.98, transport subsidy amounting to Rs. 360 crore has been released to various States/ UTs out of which Rs. 229 crore have been released for the North-Eastern Region which constitute 63% of the total releases under the scheme. The financing pattern in respect of IID centres in the North East is in the ratio of 4:1 between Government of India Grant and